

## केजरीवाल ने संघ प्रमुख भागवत को खत लिखा

पत्र लिखने का मकसद फरवरी में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व आर.एस.एस. व भाजपा के बीच मतभेद की खाई और गहरी करना

- श्री नन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जनवरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री तथा आप के संस्थापक अरविन्द केजरीवाल ने भाजपा के गलत कार्यों के खिलाफ मोहन भागवत को एक शिकायती पत्र लिखकर भाजपा और आर.एस.एस. के बीच एक बार फिर दरार पैदा करने की कोशिश की है। दिल्ली विधान सभा चुनावों से पहले, केजरीवाल ने भाजपा पर हमले तेज कर दिये हैं क्योंकि भाजपा फरवरी में होने वाले दिल्ली के चुनावों में दिल्ली की सत्ता छीनने की जबरदस्त तैयारी कर रही है। केजरीवाल ने ऐसी रणनीति गत माह उस समय अपनाई थी, जब उन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी के प्रमुख एन. चन्द्र बाबू नायडू तथा जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार को पत्र लिखे थे तथा उनसे अनुरोध किया था कि वे बाबासाहेब अम्बेडकर के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह की "अपमानजनक टिप्पणी को लेकर स्वयं को भाजपा से अलग कर लें।" केजरीवाल ने आज आर.एस.एस. प्रमुख को पत्र भेजा है तथा उनसे पूछा है कि क्या वे भाजपा के अनुचित दब-पैचों का समर्थन करते

पत्र में केजरीवाल ने भागवत के समक्ष सवाल उठाया कि क्या वे भाजपा के चुनाव जीतने के "हथकण्डों" का, जैसे वोटर में पैसा बाटना, वोटर लिस्ट में से प्रतिद्वंद्वी पार्टी के वोटरों के नाम कटवाने तथा भाजपा समर्थकों के नाम जुड़वाने का समर्थन करते हैं।

केजरीवाल ने ऐसा ही प्रयास हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू तथा जे.डी.यू.के कर्ताधर्ता नीतीश को लिखकर भी किया था।

केजरीवाल ने दोनों एन.डी.ए. गठबंधन के घटकों को पत्र लिखकर प्रेरित करने का प्रयास किया था कि उन्हें भाजपा का साथ छोड़ देना चाहिये, भाजपा नेता अमित शाह द्वारा बाबासाहेब अम्बेडकर की प्रतिष्ठा गिराते हुए अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण।

भाजपा ने प्रत्युत्तर में केजरीवाल पर आरोप लगाया कि आप व उसके नेता केजरीवाल, गैर कानूनी तरीके से रोहिण्या व बांग्लादेशियों को फर्जी दस्तावेज व धन देकर दिल्ली में बसने में मदद करते हैं, क्योंकि ये लोग आप के वोट बैंक हैं।

हैं, जो भाजपा दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये अपना रही है। केजरीवाल ने शिकायत की है कि

"भाजपा वोट खरीदने के लिये खुले आम पैसे बाँट रही है तथा मतदाता सूचियों से दलित और पूर्वोच्चल के

वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर हटाने में लगी हुई है। जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है, उसने आप और केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वे दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिण्या तथा बांग्लादेशियों की दस्तावेजों और पैसों से मदद कर रहे हैं ताकि आगामी चुनावों में उनका उपयोग अपने वोट बैंक के रूप में कर सकें।

अगर केजरीवाल का उद्देश्य एक राजनैतिक बहस छेड़ना, तथा भाजपा की अनुचित रणनीतियों पर दिल्ली के मतदाताओं के मन में भ्रम और असमंजस पैदा करना है, तो आप नेता सफल होते दिखाई नहीं देते। भागवत को लिखे उनके पत्र पर भाजपा ने तत्काल तथा तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उन्हें सलाह दी है कि वे अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिये मीडिया का ध्यान खींचने के बजाय, आर.एस.एस. से "सेवा भाव" सीखें। त्रिवेदी ने कहा कि आर.एस.एस. से सम्बद्ध संगठन, "सेवा भारती" गरीब लोगों, जिनमें कच्ची बस्तियों में रहने वाले दलित शामिल हैं, के लिये कार्य करने वाला भारत का सबसे बड़ा संगठन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## तहल्लूर राणा को अमेरिका से भारत लाया जायेगा

नई दिल्ली, 01 जनवरी। भारत को अमेरिका में बड़ी सफलता मिली है। 26/11 मुंबई हमले में शामिल पाकिस्तानी मूल के कैनडा कारोबारी तहल्लूर राणा को जल्द ही भारत लाए जाने की संभावना है। राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अमेरिकी कोर्ट ने अगस्त 2024 में फैसला सुनाते हुए भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को भारत भेजने को मंजूरी दी थी।

राणा पर आरोप है कि उसने 26/11 के मास्टरमाइंड डेविड

उसके खिलाफ 26/11 के मुंबई हमले के मास्टर माइंड डेविड हेडली की मदद करने के पुख्ता सबूत हैं।

कोलमैन हेडली की मदद की थी। हेडली ने मुंबई में ठिकानों की रेकी की थी। इससे पहले भारत ने अमेरिकी कोर्ट के समक्ष मजबूत सबूत पेश किए थे, जिनमें राणा की संलिप्तता साफ देखी गई थी। कोर्ट ने साफ किया कि राणा के खिलाफ भारत में लगे आरोप अमेरिकी अदालतों के मामलों से अलग हैं। दोनों देशों के बीच जो समझौता है उसके तहत राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। एफ.बी.आई. ने राणा को 2009 में शिकागो से गिरफ्तार किया था। अब उसे भारत लाने की तैयारी जारों पर है। कोर्ट ने राणा को आतंकवादी संगठन को मदद करने और डेनमार्क में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की नाकाम साजिश रचने के लिए दोषी करार दिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ‘भाजपा ने मेरे क्षेत्र, नई दिल्ली में “ऑपरेशन लोटस” शुरु किया है’

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 15 दिन में वोटर लिस्ट से 5,000 नाम कटवाने व 7,500 नाम जुड़वाने के आवेदन किए गए हैं

- डॉ. सतीश मिश्रा -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 1 जनवरी। मीडिया से बात करते हुये, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के चुनावों के लिये, भाजपा के पास न तो कोई विज़न है और न उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा, "भाजपा, बेईमानीपूर्ण तरीके एवं साधनों को काम में लेते हुये, किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन दिल्ली की जनता ऐसा नहीं होने देगी। जो दबपेच उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनाये थे, हम दिल्ली के चुनाव जीतने के लिये, उन्हें काम में नहीं लेने देंगे।" उन्होंने दिल्लीवासियों से कहा कि वे मतदाता सूचियों नाम चैक करते रहें।

आप नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने नई दिल्ली विधान सभा क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व वे (केजरीवाल) करते हैं, में "ऑपरेशन लोटस" शुरु किया है। केजरीवाल ने कहा, "15 दिन में, उन्होंने 5000 मतदाताओं के नाम हटाने के लिये प्रार्थना पत्र दिये हैं तथा

आप नेता एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, भाजपा ने हरियाणा व महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में जो दांवपेंच खेले, उनसे वह दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाएगी।

इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेव ने आप पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेशी चुपेपट्टियों तथा रोहिण्या शरणार्थियों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ रही है।

7500 नये नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिये आवेदन किया है। मेरे चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाता एक लाख छः हजार हैं। फिर चुनाव कराने का मतलब ही क्या है? चुनाव के नाम पर तमाशा हो रहा है।

आप नेता ने कहा कि इससे पहले "समरी रिवीजन" किया गया था तथा चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर को संशोधित मतदाता सूची जारी कर दी थी। "अगर 12 प्रतिशत अन्तर है, जैसा कि भाजपा दावा कर रही है, तो क्या चुनाव आयोग का "समरी रिवीजन"

गलत था?"

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा की योजना है कि बाहर से लोग लाये जायें तथा उन्हें दिल्ली के मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाये।

इन आरोपों का खण्डन करते हुये, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों तथा अगले वर्ष हुये विधान सभा चुनावों के बीच दिल्ली के मतदाताओं की संख्या में बहुत बड़ा उछाल आया था। उन्होंने कहा कि ऐसा ही 2019 के आम चुनावों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ‘मणिपुर संकट कांग्रेस के पुराने पापों की देन है’

माफी मांगने के तुरंत बाद कांग्रेस को कोसा, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने

-जाल खंभाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जनवरी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य में हुई हिंसा के लिये माफी मांगने के बाद, कांग्रेस पर फलटवार करते हुये, उसे राज्य की समस्याओं के लिये दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि "वर्तमान अशांति का कारण पुराने पाप हैं।" उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में न आने का बचाव किया तथा जोर देते हुये कहा कि ये ऐतिहासिक जालीय संघर्ष कांग्रेस नेतृत्व के कारण हुये हैं। उन्होंने पुनर्वास एवं विकास के लिये अपने प्रयासों पर जोर दिया।

2023 में शुरू हुई इस हिंसा के लिए माफी मांगने वाले अपने भाषण में, उन्होंने मणिपुर में ग्रेथ एवं रिकवरी के उपायों का बखाना किया था। कांग्रेस नेता

## केन्द्र ने फसल बीमा का समय व आवंटन बढ़ाया

नई दिल्ली, 01 जनवरी। केंद्र ने बुधवार को दो फसल बीमा योजनाओं - पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यू बीसीआईएस - को वर्ष 2025-26 तक एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए 824.77 करोड़ रुपये का एक अलग कोष भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय

केन्द्र सरकार ने कहा कि दायरा बढ़ाने से 4 करोड़ और किसान लाभान्वित होंगे।

समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।

मोदी ने एक्स पर लिखा, नए वर्ष का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई-बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने की मंजूरी दी है। इससे जहाँ अनदाताओं को फसलों को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बीरेन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बार भी मणिपुर नहीं आने के कांग्रेस के आरोप के जवाब में कांग्रेस को ही दोषी ठहराया।

मुख्यमंत्री ने कहा, एक्स पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार ने यहाँ बर्मा के शरणार्थियों को बसाया तथा म्यांमार के उग्रवादियों से जो समझौता किया उसी का नतीजा है कि प्रदेश हिंसा की आग में जल रहा है।

जयराम रमेश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के हिंसा-त्रस्त मणिपुर का दौरा नहीं करने को लेकर की गई मोदी की आलोचना का जवाब देते हुये, बीरेन सिंह ने मणिपुर की वर्तमान चुनौतियों के लिये "कांग्रेस के पापों" को उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने राज्य के संघर्षों के पीछे पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय बताये।

उन्होंने "एक्स" पर जयराम रमेश को सीधे सम्बोधित करते हुये कहा, "सभी लोग, जिनमें आप भी शामिल हैं,

इस बात को जानते हैं कि मणिपुर की वर्तमान अशांति कांग्रेस द्वारा अतीत में किये गये पापों का परिणाम है।" उन्होंने बर्मा के शरणार्थियों को बसाने, तथा म्यांमार के उग्रवादियों के साथ "समंशान ऑफ ऑपरेशन्स" समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने का हवाला दिया। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि इन दोनों कामों की शुरुआत उस समय हुई थी, जब केन्द्र सरकार में पी. चिदम्बरम गृहमंत्री थे।

## अब फ्लाइट में मिलेगा वाई फाई

नई दिल्ली 1 जनवरी। अगली बार आप जब भी एयर इंडिया की फ्लाइट से टेक ऑफ करेंगे तो आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट जैसी किसी भी डिवाइस से वाई-फाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। जी हाँ, एयर इंडिया ने नए साल एक जनवरी से अपने कुछ एयरक्राफ्ट में वाई-फाई सिस्टम शुरू कर दिया है। फिलहाल यह सर्विस अभी मुंबई, दिल्ली और इन्टरनेशनल फ्लाइट में प्री में दी जा रही है। लेकिन कुछ दिनों

एयर इंडिया ने दस हजार फीट की ऊंचाई पर इंटरनेट सुविधा देने के लिए वाई फाई सर्विस शुरू की है।

बाद इसका दायरा बढ़ ते हुए यात्रियों से इसका चार्ज लेना शुरू कर दिया जाएगा।

एयर इंडिया के चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर राजेश डोगरा ने बताया कि सर्विस का फायदा प्लेने के जमीन से 10 हजार फीट की ऊंचाई पर पहुँचने के बाद से ही मिलना शुरू होगा। फ्लाइट जब टेक ऑफ और लैंड कर रही होगी, तब वाई-फाई कनेक्ट नहीं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## यूक्रेन ने यूरोप को रूस से गैस व पेट्रोल की सप्लाई का रास्ता बंद किया

रूस की गैस व पेट्रोल पाइप लाइन यूक्रेन होकर ही पश्चिमी यूरोप पहुँचती थी

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जनवरी। रूस से यूरोपियन देशों को प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति करने वाली पाइप लाइन्स को यूक्रेन ने बंद कर दिया है। इन्हें लम्बे समय से पश्चिमी यूरोप के लिए बेहतर संवेदनशील माना जा रहा था, क्योंकि कोई भी छोटी सी गड़बड़ी बड़ा विनाश कर सकती थी।

इसने रूस यूक्रेन संघर्ष को और भी हाई पिच पर पहुँचा दिया है। रूस तेल और गैस सैक्टर से ही प्रतिबंधों का दबाव झेल रहा है, जिसकी वजह से रूस अपना तेल नहीं बेच पा रहा है। रूस से तेल और गैस खरीद पर प्रतिबंध ने रूस के विकल्प सीमित कर दिए हैं।

इन प्रतिबंधों से भी आगे बढ़कर यूक्रेन ने पाइप लाइन बंद कर दी है, जिससे जो चंद यूरोपियन देश रूस से गैस खरीद रहे थे, उन्हें भी आपूर्ति बंद हो गई है। इन कुछ नॉर्थ यूरोपियन देशों ने रूस की गैस पर निर्भरता कम करने

गैस पाइप लाइन बंद करने से रूस की आर्थिक नुकसान (5 अरब डॉलर) तो होगा ही, साथ ही इस बर्फीली सर्दी के मौसम में पश्चिमी यूरोप के देशों में धरो को गर्म करने में जरूरी रूसी गैस की सप्लाई से वंचित रहना पड़ेगा।

कई पश्चिमी यूरोप के देश, रूस से गैस प्राप्त करने के लिये वैकल्पिक रास्ता ढूँढ़ने को मजबूर हैं, जैसे टर्की होकर नई पाइप लाइन बिछाना, पर, नई पाइप लाईन के अपने जोखिम हैं तथा नई पाइप लाइन फटाफट नहीं बिछाया जा सकती।

सबसे ज्यादा समस्या जर्मनी के सामने है, क्योंकि, एंजिला मार्केल के चांसलरशिप के समय, जर्मनी ने, अपने लिये गैस के सारे रास्ते बंद करके, केवल रूस से आने वाली गैस पर निर्भर हो गई थी।

के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अपना लिए हैं।

जर्मनी एक प्रमुख उदाहरण है, जो एंजेल मार्केल के शासन में ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर था, पर अब उसने अन्य विकल्प

अपनाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन ने कहा है कि उसने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर गैस सप्लाई रोक दी है। रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। तब से ही पाइप लाइन बंद होने की आशंका थी। इस कदम से रूस

की बेचनी और बढ़ जाएगी। यूक्रेन से गुजरने वाली पाइप लाइन के जरिए रूस एक साल में 5 अरब डॉलर की गैस बेचता है। इसी पाइप लाइन से गैस मध्य व दक्षिणी यूरोप के कई देशों तक पहुँचती है। अब से यूक्रेन ने पाइप लाइन बंद कर दी है तो इन देशों को कड़कें की ठंड में पावर ब्लैक आउट का सामना करना पड़ सकता है।

प्राकृतिक गैस आपूर्ति में बाधा पड़ने से इसके दाम भी बढ़ जाएंगे, इससे इन देशों में सरकारों के खिलाफ असंतोष भड़केगा।

यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के लिए यूक्रेन रूस को महत्वपूर्ण लिंक के रूप में देखा जाता था, लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। इस पाइप लाइन के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ था। यूक्रेन पाइप लाइन बंद करने और अपने क्षेत्र से आपूर्ति की अनुमति नहीं देने की धमकी दे रहा था। रूस की प्राकृतिक तेल एवं गैस कम्पनी गैज़प्रॉम ने रूस से पश्चिमी यूरोप तक गैस भेजने के लिए पाइप लाइन बिछाने का अनुबंध किया था। इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## बराड़ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने

नयी दिल्ली, 01 जनवरी। सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ को उसी न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने के निर्णय की बुधवार को घोषणा की। विधि एवं न्याय मंत्रालय की एक विज्ञापन में कहा गया है, राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ को उसी न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति बराड़ की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।